

अनिल झालानी

101, “देवप्रस्थ”, पावर हाउस रोड,

रतलाम (म.प्र.) 457001

☎ : 074 12 (O)270216, (R)270217

मो. 9300223310

प्रति,

महामहिम श्री प्रणव मुखर्जी जी  
भारत के राष्ट्रपति,  
नई दिल्ली

प्रति,

माननीय श्री मनमोहन सिंह जी  
प्रधानमंत्री भारत सरकार,  
नई दिल्ली

विषय :- भारत रत्न की पात्रता – एवं वापसी

मान्यवर महोदय,

भारत रत्न से अलंकृत एवं सम्मानित करने के पीछे यही भावना रहती है कि देश के प्रति संबंधित महानुभाव का कितना अमूल्य योगदान रहा। किन्तु जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च पदो पर पहुंच चुका हो और देशवासियो ने उस व्यक्ति को उच्चतम शिखर पर बिठाया वह उसके योगदान के पुरुस्कार स्वरूप ही है। यदि उसके पश्चात् कुछ भी उनकी विशेष उपलब्धी पद पर रहते हुए हुई है वह उस पद पर रहने से ही संभव हो पाई है। सर्वोच्च पदो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के रूप मे विश्व की जनता उन्हे स्वाभाविक रूप से दीर्घकाल तक स्मरण करती रहेगी।

अतः इस विषय मे मंथन, चिंतन एवं योग्य निर्णय लेने की आवश्यकता है कि उक्त संवैधानिक पदो पर जो भी शख्स पदासीन रहा हो उन्हे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ प्रदान करने की आवश्यकता ही नहीं है और डॉ

अनिल झालानी

101, “देवप्रस्थ”, पावर हाउस रोड,  
रतलाम (म.प्र.) 457001

☎ : 07412 (O)270216, (R)270217  
मो. 9300223310

राजेन्द्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ राधाकृष्णन,, श्री लालबहादुर शास्त्री, डॉ जाकीर हुसैन, श्री वीवी गिरी, श्री मति इंदिरागांधी, श्री राजीव गांधी, श्री मोरारजी देसाई, डॉ. अब्दुल कलाम आदि को भारत रत्न की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पद पर विराजित एवं इन पदों को सुशोभित करने वाला व्यक्ति भी तो सर्वोच्च नागरिक होते हुए अतिसम्मानित एवं अतिविशिष्ट होते हुए भारत रत्न ही हुए।

अतः एक कठोर, अप्रिय किन्तु व्यवहारिक कदम उठाते हुए भारत में सभी भूतपूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति पदों पर आसीन विभूतियों के न केवल भारत रत्न सम्मान वापस लिया जाना चाहिये बल्कि भविष्य में यदि भारत रत्न से पूर्व में ही सम्मानित हो चुके किसी व्यक्ति को इन उच्च पदों पर शपथ दिलाई जाती है तो उससे पूर्व यह सम्मान वापस भी लिया जाना चाहिये।

भारत रत्न से सम्मानित सर्वोच्च नागरिक गौर राजनैतिक होने पर ही निर्विवादित और सर्वसम्मानित हो सकता है। भारत रत्न यदि किसी खिलाड़ी को देने का प्रावधान नहीं था तो यह भी प्रावधान होना चाहिये कि किसी सक्रिय राजनीतिज्ञ को न दिया जावे। भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण सहित सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने वाली समिति निर्वाचन आयोग सर्वोच्च, न्यायालय व सीबीआई की भांति स्वतंत्र व निष्पक्ष एंजेंसी के रूप में गठित होनी चाहिये। इति, दिनांक :19/11/2013

भवदीय

  
अनिल झालानी